RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी. ओफिस : १३१, धर्मनगर सोसायटी, हाईवे रोड, साबरमती, अहमदाबाद- ३८० ००५. गुजरात, भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 212 | दि. 02-12-2018 रविवार | वि.सं. 2075 | कारतक वद-10 | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

युपीए ने की थी तीन सर्जिकल स्ट्राइक : कांग्रेस अध्यक्ष

मोदी ने सैन्य फैसले को बनाया राजनीतिक संपत्ति : राहुल गांधी

(संपूर्ण समाचार सेवा)
उदयपुर, १ दिसम्बर।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सैन्य फैसले को भी राजनीतिक संपत्ति बना दिया है, जबकि यही काम पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार ने तीन बार किया था। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री ने सेना के अधिकार क्षेत्र में घुसते हुए उनकी सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक संपत्ति में बदल दिया जबकि वास्तव में यह एक सैन्य फैसला था। उदयपुर के एक कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में हार सामने दिखी तो मोदी ने एक सैन्य संपत्ति को राजनीतिक संपत्ति में बदल दिया। उन्होंने कहा, क्या आपको पता है कि मनमोहन सरकार ने भी तीन बार सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भाषण में बीजेपी पर हमलावर होकर राहुल ने कहा, हम सैन्य मामलों में सेना की सुनते हैं, उनकी मानते हैं जबकि राजनीति मामलों

यूपीए ने जब मोदी जी को सरकार सौंपी तब एनपीए दो लाख करोड़ रुपये था जो चार साल में बढ़कर १२ लाख करोड़ रुपये हो गया है : राहुल

में उसे प्रवेश की अनुमति नहीं देते। लेकिन प्रधानमंत्री ने सेना के अधिकार क्षेत्र (डोमेन) में घुसते हुए उनकी सर्जिकल स्ट्राइक को राजनीतिक संपत्ति (एसेट) में बदल दिया, जबकि वास्तव में यह एक सैन्य फैसला था। गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को लगता है कि दुनिया का सारा ज्ञान उनके ही दिमाग से आता है और बाकी दुनिया को कुछ नहीं मालूम है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यहां बैंकों के बकाया कर्ज को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए ने जब मोदी जी को सरकार सौंपी तब एनपीए दो लाख करोड़ रुपये था जो चार साल में बढ़कर १२ लाख करोड़ रुपये हो गया है। राहुल ने नोटबंदी को ऐसा घोटाला बताया जिसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और दुकानों की रीढ़ तोड़ना था। राहुल ने कहा नोटबंदी और जीएसटी को लेकर हिंदुस्तान की जनता भ्रमित है। उन्होंने कहा, नोटबंदी एक घोटाला था और इसका लक्ष्य सूक्ष्म व लघु कारोबार की, दुकानदारों की रीढ़ तोड़ना था। गांधी ने कहा कि वे उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है लेकिन चाहते हैं कि अगर मोदी सरकार ने १५ लोगों के साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए माफ किए हैं तो हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का भी वह कर्ज माफ करे, उन्हें न्याय दे। आज देश बेरोजगारी की समस्या से परेशान है और प्रधानमंत्री रोजगार का निर्माण करने में पूरी तरह से विफल हुए हैं। इस समय देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी दूर करना है। आज देश के सरकारी संस्थान सबसे बेहतर है लेकिन उन्हें २१वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से ढालने की जरूरत है।

अमित शाह ने किया कांग्रेस पर पलटवार

नरेन्द्र मोदी ने शहीद जवानों का बदला लिया : अमित शाह

आज सीमा पर तैनात जवान के दिल में भरोसा है कि मेरी सरकार, मेरे पीछे चट्टान की तरह खड़ी है : शाह

(संपूर्ण समाचार सेवा)
जोधपुर, १ दिसम्बर।

राजस्थान में ७ दिसंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक दल एक-दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। सवाल गोत्र पर हो रहा है और सर्जिकल स्ट्राइक भी चुनावी हमले से अछूती नहीं है। उदयपुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सर्जिकल स्ट्राकि को लेकर निशाना साधा तो फलौदी में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इसका जवाब दिया।

चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद जवानों का बदला लिया। राहुल गांधी बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिये हमने सर्जिकल स्ट्राइक की...आप देश के शहीदों का अपमान करते हैं, आप में तो हिम्मत नहीं थी। शाह के मुताबिक, आज सीमा पर तैनात जवान के दिल में एक भरोसा है कि मेरी सरकार, मेरे पीछे एक चट्टान की तरह खड़ी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इससे पहले उदयपुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि प्रधानमंत्री

ने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सैन्य फैसले को भी राजनीतिक संपत्ति बना दिया है जबकि यह काम तो पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार तीन बार कर चुकी थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, एक ओर तो मोदी ने नेतृत्व में देशभक्तों की टोली है तो दूसरी ओर राहुल के नेतृत्व में सत्ता का उपभोग करने वालों की टोली, जिसके पास ना नेता है, ना नीति है और ना सिद्धांत। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं किए जाने पर तंज कसते हुए अमित शाह ने कहा, जिस सेना का सेनापति ही तय नहीं, वह विजय कैसे प्राप्त कर सकती है।

लगातार १०वें दिन उपभोक्ताओं को राहत मिली

पेट्रोल और डीजल कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी

(संपूर्ण समाचार सेवा)
नई दिल्ली, १ दिसम्बर।

पेट्रोल और डीजल के दाम शनिवार को लगातार १०वें दिन उपभोक्ताओं को राहत मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले एक

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार गिरावट

महीने में दिल्ली में पेट्रोल ६.५४ रुपए और डीजल ६.४३ रुपए प्रति लीटर सस्ता हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में शुक्रवार को फिर कच्चे तेल के दाम में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। तेल विपणन कंपनियों ने दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल के भाव में ३४ पैसे प्रति लीटर की कटौती की, जबकि कोलकाता में पेट्रोल ३३ पैसे और चेन्नई में ३६ पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ। डीजल के दाम में दिल्ली में ३७ पैसे, कोलकाता में ४९ पैसे, मुंबई में ३९ पैसे और चेन्नई में ४० पैसे प्रति लीटर की कटौती की गई। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में शनिवार को पेट्रोल के भाव क्रमशः ७२.४३ रुपए, ७४.५५ रुपए, ७८.०९ रुपए और ७५.२६ रुपए प्रति लीटर दर्ज किए गए। चारों महानगरों में डीजल की कीमते क्रमशः ६७.३५ रुपए, ६९.०८ रुपए, ७०.५० रुपए और ७१.१२ रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई। विदेशी वायदा एक्सचेंजों पर सबसे सक्रिय वायदा सौदे में ब्रेट क्रूड का भाव ५९.१९ डॉलर प्रति बैरल और डबल्यूटीआई का भाव ५०.७० डॉलर प्रति बैरल बंद हुआ। एंजेल ब्रोकिंग हाउस के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता (कमोडिटी रिसर्च) ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का भाव और दो से तीन रुपए कम हो सकता है, क्योंकि अंतराष्ट्रीय बाजार में अक्टूबर में चार साल के उच्च स्तर पर जाने के बाद ब्रेंट क्रूड में करीब २७ डॉलर प्रति बैरल की कमी है। उन्होंने कहा कि कच्चा तेल सस्ता होने से डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ है और आयात बिल इजाफा होने से चालू खाते का घाटा बढने की चिंता भी अब कम होगी।

कई केसों में आर्मी ने जांच नहीं की : सुप्रीम

एफआईआर के खिलाफ ७०० सैनिकों की याचिका खारिज

(संपूर्ण समाचार सेवा)
नई दिल्ली, १ दिसम्बर।

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर जैसे अशांत क्षेत्रो में एनकाउंटर को अंजाम देने वाले सैन्य कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका ७०० सैन्य कर्मियों की तरफ से दाखिल की गई थी। इन क्षेत्रो में सेना को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऐक्ट के तहत विशेष अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि १५-२० साल पुराने कई केसों में आर्मी ने जांच भी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर और यूयू ललित ने कहा, अशांत क्षेत्रों में सैनिकों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को ह समझते है। इसलिए हम लोग कई बार अटॉर्नी जनरल से १५-२० साल में हुए फर्जी एनकाउंटर मामलों की जांच के लिए कह रहे हैं। जब हमने पाया कि इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है तो, हमने कुछ भी नहीं हुआ है तो, हमने कुछ मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। खास तौर पर उन मामलों में जिनमें पहली नजर में ही हाई कोर्ट, न्यायिक आयोग और जस्टिस संतोष हेगड़े कमिशनर या एनएचआरसी में फर्जी एनकाउंटर का अंदेशा होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर ऐक्ट के तहत सही एनकाउंटर में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह अपने ८ जुलाई, २०१६ और १४ जुलाई, २०१७ के डैसलों को बदलने के मुड में नहीं है, जिसमें १०० सैन्य कर्मियों के खिलाफ १५२८ केसों मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार महेता ने कहा कि ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अशांत इलाको में ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा।

भगोड़े आर्थिक अपराधियों पर कसेगी नकेल

जी-२० में पीएम मोदी ने पेश किया ९ सूत्रीय अजेंडा

(संपूर्ण समाचार सेवा)
ब्यूनस आयर्स (अर्जेंटीना, १ दिसम्बर।

हाल में भारतीय बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर विदेश भागने वाले आर्थिक अपराधियों पर केंद्र सरकार ने लगान कसने की तैयारी शुरु कर दी। ऐसे अपराधों को रोकने के साथ ही भगोडें आर्थिक अपराधियों को कानून के कठघरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने जी-२० देशों के साथ मिलकर एक ठोस पहल की है। भारत ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने, उनकी पहचान, प्रत्यर्पण और उनकी संपत्तियों को जब्त करने के लिए जी-२० देशों से एक मजबूत और सक्रिय सहयोग मांगा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय वित्त और कर प्रणाली पर जी-२० शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र में आर्थिक अपराधियों के खिलाफ ९ सूत्रीय अजेंडा पेश करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भगोड़े आर्थिक अपराधियों को प्रवेश देने और सुरक्षित पनाहगाह पाने से रोकने के लिए सदस्य देशों द्वारा संयुक्त प्रयास से एक तंत्र व प्रक्रिया बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि जी-२० फोरम को अपने देश में लिए गए भारी कर्ज को चुकाए बिना दूसरे देशों में पनाह लेने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों की पहचान करने के लिए काम शुरू करने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा, कानूनी प्रक्रियाओं में सहयोग जैसे अपराधियों की संपत्ति को जब्त करना और उनके स्वदेश प्रत्यार्पण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सिद्धांतो (यूएनसीएसी) और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध (यूएनओटीसी) के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संधिपत्र, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित सिद्धांतों को पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगोड़े आर्थिक अपराधियों की एक मानक परिभाषा तय करने का काम फाईनैंशल ऐकशन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) कौ सौंपा जाना चाहिए। एफएीएफफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने को लेकर उनकी पहचान, उनका प्रत्यर्पण और उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मानक प्रक्रियाएं तय करनी चाहिए, जिस पर सबकी सहमति हो। इससे जी-२० देशों में ऐसे मामलों से निपटने में सहायता मिलेगी। भारत ने प्रत्यर्पण के सफल मामलों, प्रत्यर्पण की मौजूदा प्रणाली में खामी और कानूनी सहायता इत्यादि को लेकर अनुभवों को साझा करने के लिए एक साझा प्लेटफॉर्म बनाने की भी वकालत की है। साथ ही यह भी कहा गया है कि जी-२० फोरम को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों का पता लगाने पर विचार करने का काम शुरू करना चाहिए।

डीएसी ने रक्षा खरीद को मंजूरी दी

ब्राह्मोस-एआरवी की ३००० करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी

मीटिंग रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई

(संपूर्ण समाचार सेवा)
नई दिल्ली, १ दिसम्बर।

डिफेंस एक्विजिशन कमिटी (डीएसी) ने शनिवार को ३००० करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी दे दी है। इसमें दो युद्धपोत के लिए ब्राह्मोस मिसाइल और बैटल टैंक अर्जुन के लिए आर्मर्ड रिकवरी वीइकल (एआरवी) की खरीद शामिल है। डीएसी की मीटिंग रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। बता दें कि अक्टूबर में कैबिनेट ऑन सिक्यॉरिटी (सीसीए) ने पी ११३५.६ (शिप फॉलोऑन) की खरीद का फैसला लिया था। डीएसी ने दो नेवी शिप के लिए ब्राह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी है। नेवी शिप रूम में बनेंगे। स्वदेश में डिजाइन होने वाले ब्राह्मोस टेस्ट की जा चुकी है।

डीएसी ने थल सेना के बैटल टैंक अर्जुन के लिए एआरवी की खरीद को भी मंजुरी दी है। इन्हें डीआरडीओ (डिफेंस रिसर्च ऐंड डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) ने डिजाइन किया है और ये सरकार उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैकचर किए जाएंगे।

ड्रोन पोर्टस से आसान होगी ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन की राह

(संपूर्ण समाचार सेवा)
नई दिल्ली, १ दिसम्बर।

ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैफिक की समस्या से निपटते हुए ड्रोन की मदद ली जाएगी। केंद्री नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि अथॉरिटी हॉस्पिटलों में ड्रोनपोर्टस बनाने की तैयारी कर रही है। बड़े ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन १ दिसंबर से शुरू होगा। उन्होंने कहा, इसके लिए एक महीने के बाद लाइसेंस इश्यू करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हम अपनी ड्रोन पॉलिसी २.० पर काम कर रहे हैं। जिसके तहत ड्रोन को नजर से दूर रखकर उड़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया बड़े हॉस्पिटल के बीच एक कोरिडोर बनाने पर भी विचार चल रहा है।

विमान ईंधन ११ फीसदी सस्ता, कंपनियों को राहत

(संपूर्ण समाचार सेवा)
नई दिल्ली, १ दिसम्बर।

वित्तीय संकट से जूझ रही देश की विमान सेवा प्रदाता कंपनियों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। तेल कंपनियों ने शनिवार को विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में लगभग ११ फीसदी कटौती की घोषणा की है। दिसंबर में दिल्ली और मुंबई में एक किलो लीटर जेट फ्यूल की कीमत क्रमशः ६८,०५०.९७ रुपये और ६७,९७९.५८ रुपये हो गई है, जो पिछले महीने क्रमशः ७६,३८० रुपये और ७६,०१३.२ रुपये पर थी। जेट फ्यूल चूंकि ब्रेंट क्रूड से जुड़ा है, इसलिए उड्डयन मंत्रालय काफी लंबे वक्त से इसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहा है, तेल कंपनियों ने शनिवार को विमान ईंधन (एटीएफ) की कीमत में लगभग ११ फीसदी कटौती की घोषणा की है। जेट फ्यूल चूंकि ब्रेंट क्रूड से जुड़ा है, इसलिए उड्डयन मंत्रालय काफी लंबे वक्त से इसे जीएसटी के दायरे में लाने की मांग कर रहा है,ताकि विभिन्न राज्यों में इस पर लगने वाले अलग अलग कर की दरों से राहत मिल सके।

मानवेंद्र सिंह ने वसुंधरा पर प्रतिक्रिया

वसुंधरा को हराना मुश्किल मैं यहा जीतने के लिए हूं

(संपूर्ण समाचार सेवा)
झालावाड़, १ दिसम्बर।

राजस्थान की चुनावी लड़ाई में अति उत्सुकता भरा मुकाबला लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके गढ़ में हराना मुश्किल काम है, लेकिन वह लड़ने और जीतने के लिए यहां है। झालावाड़ आजाद होगा नारे के साथ सिंह ने कहा कि वह अपनी प्रबल प्रतिद्वंद्वी को चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूर्व बीजेपी नेता जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह ने कहा, मैं सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने के लिए यहां हूं। चुनाव से कुछ हफ्ते पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र ने कहा कि जब उन्हें मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने एक सेकंड में इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। यह पूछ जाने पर कि क्या वह इस चुनाव को डेविड और गोलिएथ के युद्ध की तरह देख रहे है, सिंह ने इसका जवाब न में दिया। उन्होंने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि यह मुश्किल काम हैं। मैं इस चुनौती को कम करके नहीं आंक रहा हूं। मैं खुद को डेविड बिल्कुल नहीं मानता। वसुंधरा राजे यहां से तीन बार विधायक होने के अलावा पांच बार सांसद भी रह चुकी है। यह पूछ जाने पर कि क्या वह इस चुनाव को डेविड और गोलिएथ के युद्ध की तरह देख रहे है, सिंह ने कहा, उनके पास ३० साल का अनुभव है और मुझे १५ दिन में उन ३० वर्षो को पाटना होगा। इसलिए यह एक चुनौती है जिसके लिए मैं तैयार हूं। खुद के बाहरी होने के विरोधियों के दावे को खारिज करते हुए सिंह ने कहा कि झालवाड़ के लोग उन्हें खुले दिल और पूरी गर्मजोशी से स्वीकर कर चुके है। यह पूछ जाने पर कि क्या वह इस चुनाव को डेविड और गोलिएथ के युद्ध की तरह देख रहे हैउन्होंने कहा कि लोगों को यह जानने में एक-दो-तीन से ज्यादा समय नहीं लगता कि कोई उनसे संबंध रखता है या नहीं।

संपादकिय

कॉरिडोर और कूटनीति

(जी.एन.एस.), आतंकवाद को औजार बनाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं, लेकिन सांस्कृतिक आदान–प्रदान बनाए रखने की सोच वाले लोगों की तादाद करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।श्री करतारपुर साहिब के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सुरक्षित कॉरिडोर की नींव दोनों तरफ रख दी गई। सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर जिले के मान गांव में उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका शिलान्यास किया, जबकि बुधवार को पाकिस्तान में इसकी बुनियाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने रखी। इस अवसर पर भारत से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और हरसिमरत कौर के साथ–साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां मौजूद थे। इस गलियारे के निर्माण को लेकर भारतीय राजनीतिक वर्ग के रवैये से पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ–साथ उन लोगों का उत्साह भी थोड़ा फीका पड़ा, जो दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्तों के हिमायती हैं। कम से कम इस मौके को कूटनीति से परे रखा जा सकता था। सोमवार को शिलान्यास समारोह में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भारतीय जवानों की मौत के लिए जवाबदेह ठहराया। उन्होंने कहा कि बाजवा भारतीय जवानों पर हमले करवा कर बुजदिली दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण का अर्थ यह नहीं है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो जाएगी। ऐसा लगा जैसे भारतीय राजनेता अपने स्तर पर सफाई दो रहे हों कि कॉरिडोर से जोड़कर उनके प्रति कोई धारणा न बनाई जाए। क्या यह देश में चल रहे असेंबली चुनावों का दबाव है? सचाई यह है कि जनता को कोई गलतफहमी नहीं है। पाकिस्तान के रवैये को वह भी देख रही है और यह मानकर चल रही है कि दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के लिए यह सही वक्त नहीं है। लेकिन भारत के लोग, खासकर सीमा पर रहने वाले लोग यह भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जनता के स्तर पर संपर्क जारी रहे। यह भावना दोनों तरफ है। आतंकवाद को औजार बनाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं, लेकिन सांस्कृतिक आदान–प्रदान बनाए रखने की सोच वाले लोगों की तादाद करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर कड़वाहट भरी बातें इस प्रॉजेक्ट की सफलता को लेकर आशंकाएं पैदा करती हैं। मुमकिन है, पाकिस्तान ने ब्रिटेन और कनाडा के कुछ सिखों के बीच सिर उठा रहे खालिस्तानी स्वर को भांपकर उसे हवा देने के लिए ही इस कॉरिडोर पर मोहर लगाई हो। पाकिस्तान में कॉरिडोर की नींव रखे जाने के मौके पर खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला की मौजदूगी से इस संदेह को बल मिलता है। बावजूद इसके, हमारा संयम ही हमारी शक्ति है। सार्क के लिए पाक आमंत्रण को ठुकराकर भारत ने अपना कूटनीतिक स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। लेकिन कॉरिडोर जैसी 'पीपल टू पीपल' परियोजनाओं पर हमारा रवैया सकारात्मक ही होना चाहिए।

हल्की होगी पढ़ाई

(जी.एन.एस.), पहली और दूसरी के बच्चों के लिए बस्ते का वजन डेढ़ किलो और तीसरी से पांचवीं तक के बच्चों के लिए दो से तीन किलो निर्धारित किया गया है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को अब होमवर्क नहीं दिया जाएगा, खुशी की बात है कि केंद्र सरकार बच्चों के कंधों से बस्ते का बोझ कम करने को लेकर वाकई गंभीर दिख रही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कहा है कि स्कूली बच्चों के बैग का वजन कम करने के लिए भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार नियम बनाएं। अब सत्र के बीच मे दिशा निर्देश आये है, जबकि सभी किताबे खरीदी जा चुकी हैं, और अगला सत्र आने तक इन आदेशो का भी पिछले आदेशो जैसा हश्र हो जाने के पूरे चान्स हैं.इन निर्देशों में पहली और दूसरी के बच्चों के लिए बस्ते का वजन डेढ़ किलो और तीसरी से पांचवीं तक के बच्चों के लिए दो से तीन किलो निर्धारित किया गया है। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को अब होमवर्क नहीं दिया जाएगा। मंत्रालय ने इन्हें केवल गणित और भाषा पढ़ाने को कहा है, जबकि तीसरी से पांचवीं कक्षा के स्टूडेंट्स को गणित, भाषा और पर्यावरण विज्ञान पढ़ाने का निर्देश दिया गया है। प्राइमरी शिक्षा में निश्चय ही यह एक बड़ा सुधार है, बशर्ते यह लागू हो जाए। स्कूल बैग का वजन कम करने को लेकर नियम पहले से ही बने हुए हैं पर वे लागू नहीं हो पाए। गौरतलब है कि 1993 में यशपाल कमिटी ने प्रस्ताव रखा था कि पाठ्य पुस्तकों को स्कूल की संपत्ति समझा जाए और बच्चों को अपनी किताबें क्लास में ही रखने के लिए लॉकर्स अलॉट किए जाएं। वर्ष 2005 में नैशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (एनसीएफ) ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें बच्चों के शारीरिक और मानसिक दबाव को कम करने के सुझाव दिए गए थे। इसके आधार पर एनसीईआरटी ने नए पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार कीं, जिसे सीबीएसई से संबद्ध कई स्कूलों ने अपनाया। उसके बाद चिल्ड्रन्स स्कूल बैग एक्ट, 2006 के तहत कहा गया कि बच्चों के स्कूल बैग का वजन उनके शरीर के कुल वजन के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। इन सब उपायों के बावजूद आज भी ज्यादातर स्कूली बच्चों को भारी बोझा अपनी पीठ पर ढोना पड़ता है। स्कूल चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, हकीकत यही है कि जिस स्कूल का बस्ता जितना ज्यादा भारी होता है और जहां जितना ज्यादा होमवर्क दिया जाता है, उसे उतना ही अच्छा स्कूल माना जाता है। शरीर विज्ञानी चेतावनी दे चुके हैं कि भारी बस्ता बच्चों की हड्डियों में विकृति पैदा करता है और बड़े होने पर वे गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। शिक्षा शास्त्री बताते हैं कि 4 से 12 साल तक की उम्र बच्चे के व्यक्तित्व के विकास की उम्र होती है, इसलिए इस दौरान रटंत पढ़ाई का बोझ डालने के बजाय सारा जोर उसकी रचनात्मकता को विकसित करने पर होना चाहिए। अच्छा है कि सरकार ने विशेषज्ञों की इस राय पर ध्यान दिया और शुरुआती कक्षाओं में सिलेबस का बोझ कम करने का निर्णय किया।

उम्मीद करें कि राज्य सरकारें उसके निर्देशों की रोशनी में नियम बनाएंगी। पब्लिक स्कूलों के संचालकों, शिक्षकों और उन अभिभावकों को भी इन नियमों को मन से स्वीकार करना होगा, जो बच्चों को अधिक से अधिक पाठ रटा देने को ही क्वालिटी एजुकेशन मान बैठे हैं।

निजी अस्पतालों में पैसा कमाने के लिए सी–सेक्शन से प्रसव की संख्या अधिक ~ आईआईएम–ए अध्ययन

अहमदाबाद, दो दिसंबर (भाषा) भारत में एक साल में निजी अस्पतालों में हुए 70 लाख प्रसवों से से नौ लाख प्रसव बगैर पूर्व योजना के सीजेरियन सेक्शन (सी–सेक्शन) के जरिए हुए जिन्हें "रोका" जा सकता था और ये ऑपरेशन मुख्यत~ पैसा कमाने के लिए किए गए। भारतीय प्रबंधन संस्थान–अहमदाबाद (आईआईएम–ए) ने एक अध्ययन में यह कहा है। शिशुओं के "चिकित्सीय रूप से अनुचित" ऐसे जन्म से ना केवल लोगों की जेब पर बोझ पड़ता बल्कि इससे "स्तनपान कराने में देरी हुई, शिशु का वजन कम हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई।" इसके अलावा नवजातों को अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ा। आईआईएम–ए के फैकल्टी सदस्य अंबरीश डोंगरे और छात्र मितुल सुराना ने यह अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि "जो महिलाएं प्रसव के लिए निजी अस्पतालों का चयन करती हैं उनमें सरकारी अस्पतालों के मुकाबले बगैर पूर्व योजना के सी–सेक्शन से बच्चे को जन्म देने की आशंका 13.5 से 14 फीसदी अधिक होती है।" ये आंकड़ें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के 015–16 में हुए चौथे चरण पर आधारित हैं जिसमें पाया गया कि भारत में निजी अस्पतालों में 40.9 फीसदी प्रसव सी–सेक्शन के जरिए हुए जबकि सरकारी अस्पतालों में यह दर 11.9 प्रतिशत रही।अध्ययन में कहा गया है कि सी–सेक्शन के जरिए नवजातों का जन्म कराने के पीछे मुख्य वजह "वित्तीय लाभ" कमाना रहा। एनएफएचएस का हवाला देते हुए आईआईएम–ए के अध्ययन में कहा गया है कि किसी निजी अस्पताल में प्राकृतिक तरीके से प्रसव पर औसत खर्च 10,814 रुपये होता है जबकि सी–सेक्शन से 23,978 रुपये होता है। अध्ययन में कहा गया है, "चिकित्सीय तौर पर स्पष्ट किया जाए तो सी–सेक्शन से प्रसव से मातृ और शिशु मृत्यु दर और बीमारी से बचाव होता है लेकिन जब जरुरत ना हो तब सी–सेक्शन से प्रसव कराया जाए तो इससे मां और बच्चे दोनों पर काफी बोझ पड़ता है जो जेब पर पड़ने वाले बोझ से भी अधिक होता है।" इसमें कहा गया है कि सी–सेक्शन से प्रसव की संख्या कम करने के लिए सरकार को ना केवल उपकरणों और कर्मचारियों के लिहाज से बल्कि अस्पताल के समय, सेवा प्रदाताओं की अनुपस्थिति और बर्ताव के लिहाज से भी सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं को मजबूत करना होगा।

कॉरिडोर और कूटनीति

(जी.एन.एस.),आतंकवाद को औजार बनाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं, लेकिन सांस्कृतिक आदान–प्रदान बनाए रखने की सोच वाले लोगों की तादाद करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।श्री करतारपुर साहिब के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक सुरक्षित कॉरिडोर की नींव दोनों तरफ रख दी गई। सोमवार को पंजाब के गुरदासपुर जिले के मान गांव में उपराष्ट्रपति वैंकेया नायडू और सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसका शिलान्यास किया, जबकि बुधवार को पाकिस्तान में इसकी बुनियाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने रखी। इस अवसर पर भारत से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और हरसिमरत कौर के साथ–साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी वहां मौजूद थे। इस गलियारे के निर्माण को लेकर भारतीय राजनीतिक वर्ग के रवैये से पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ–साथ उन लोगों का उत्साह भी थोड़ा फीका पड़ा, जो दोनों मुल्कों के बीच बेहतर रिश्तों के हिमायती हैं। कम से कम इस मौके को कूटनीति से परे रखा जा सकता था। सोमवार को शिलान्यास समारोह में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पाक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को भारतीय जवानों की मौत के लिए जवाबदेह ठहराया। उन्होंने कहा कि बाजवा भारतीय जवानों पर हमले करवा कर बुजदिली दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भी आतंकवाद का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण का अर्थ यह नहीं है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो जाएगी। ऐसा लगा जैसे भारतीय राजनेता अपने स्तर पर सफाई दो रहे हों कि कॉरिडोर से जोड़कर उनके प्रति कोई धारणा न बनाई जाए। क्या यह देश में चल रहे असेंबली चुनावों का दबाव है? सचाई यह है कि जनता को कोई गलतफहमी नहीं है। पाकिस्तान के रवैये को वह भी देख रही है और यह मानकर चल रही है कि दोनों देशों के रिश्ते सुधारने के लिए यह सही वक्त नहीं है। लेकिन भारत के लोग, खासकर सीमा पर रहने वाले लोग यह भी चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जनता के स्तर पर संपर्क जारी रहे। यह भावना दोनों तरफ है। आतंकवाद को औजार बनाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं, लेकिन सांस्कृतिक आदान–प्रदान बनाए रखने की सोच वाले लोगों की तादाद करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर कड़वाहट भरी बातें इस प्रॉजेक्ट की सफलता को लेकर आशंकाएं पैदा करती हैं। मुमकिन है, पाकिस्तान ने ब्रिटेन और कनाडा के कुछ सिखों के बीच सिर उठा रहे खालिस्तानी स्वर को भांपकर उसे हवा देने के लिए ही इस कॉरिडोर पर मोहर लगाई हो। पाकिस्तान में कॉरिडोर की नींव रखे जाने के मौके पर खालिस्तान समर्थक गोपाल चावला की मौजदूगी से इस संदेह को बल मिलता है। बावजूद इसके, हमारा संयम ही हमारी शक्ति है। सार्क के लिए पाक आमंत्रण को ठुकराकर भारत ने अपना कूटनीतिक स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। लेकिन कॉरिडोर जैसी 'पीपल टू पीपल' परियोजनाओं पर हमारा रवैया सकारात्मक ही होना चाहिए।

जी–20 के कष्ट

(जी.एन.एस.), दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी–20 की सालाना शिखर बैठक इस बार गंभीर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आज से ही शुरू होने जा रही है।

ताकतवर देशों का संकीर्ण नजरिया

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह जी–20 की सालाना शिखर बैठक इस बार गंभीर अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में आज से ही शुरू होने जा रही है। दो दिन की इस बैठक में विश्व अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद चुनौतियों का कोई हल निकल पाता है या नहीं, इसका पता बैठक के बाद ही चलेगा लेकिन पिछले कुछ समय से दिख रहे बड़े राजनेताओं के व्यवहार को कसौटी मानें तो कहना होगा कि इस बैठक से कोई बड़ी उम्मीद नहीं बांधी जा सकती। जी–20 की आर्थिक शक्ति जगजाहिर है। सकल वैश्विक उत्पाद (जीडब्ल्यूपी) का 85 फीसद और विश्व व्यापार का 80 फीसद हिस्सा इस संगठन के दायरे में आता है। ऐसे में अगर जी–20 से यह उम्मीद की जाती है कि विश्व अर्थव्यवस्था का रास्ता रोके खड़ी अड़चनों से निपटने की सटीक रणनीति बनाकर उस पर अमल भी सुनिश्चित करेगा तो इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं है।

विश्व का बड़ा भूभाग यानी एक को छोड़ सामग्र अफ्रीका जी–20 से बाहर है उनकी समस्या कौन और कैसे रखी जाय? गौर करें अपने निकतम पड़ोसी पाकिस्तान की जिसके कॅप्टन आज इमरान ख़ान है सभी कॉमेंट्स देखेंकॉमेंट लिखें 2008 में जब दुनिया मंदी की गिरफ्त में आई थी तो उससे बाहर निकलने में सबसे अहम भूमिका जी–20 ने ही निभाई थी लेकिन उस वक्त प्रमुख देशों के नेताओं में जो तालमेल दिखा, उसके दोहराव के आसार आज कहीं दूर–दूर तक दिखाई नहीं देते। इसके उलट आज लगभग सारे ही ताकतवर देशों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। हाल यह कि पुराने संकट हल करना तो दूर, नए संकट खड़े करने में भी इन्हें कोई हिचक नहीं होती। यूक्रेन के मसले पर रूस और ईयू आमने–सामने हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप किस मसले पर कैसा रुख दिखाएंगे, कोई नहीं जानता। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर फिलहाल जोरों पर है। जर्मनी और यूरोपियन यूनियन से अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्तों की तल्खी समय–समय पर सार्वजनिक रूप से छलकती रही है। सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में डॉनल्ड ट्रंप भले ही सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के बचाव में खुलकर सामने आ गए हों पर अभी तो उनके लिए अपना खुद का बचाव करना ही कठिन हो गया है। ऐसे में देखने की बात यही है कि अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में होने वाली यह बैठक विश्व अर्थव्यवस्था में तेजी का कोई रास्ता सुझाती है या झगड़ा–झंझट के लिए ही इसको इतिहास में दर्ज किया जाता है। बैठक से ठीक पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की अध्यक्ष क्रिस्टीन लगार्ड ने जी–20 के नेताओं को आगाह किया है कि अगर विश्व व्यापार की अड़चनों और ब्रेग्जिट जैसे मसलों से ठीक ढंग से नहीं निपटा गया तो विश्व अर्थव्यवस्था का संकट और गहरा सकता है। ध्यान रहे कि डॉनल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नौकरियां बचाने की आक्रामक रणनीति के तहत विदेशी कारों पर आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी दी है। क्रिस्टीन लगार्ड ने साफ कहा है कि ऐसा हुआ तो विश्व अर्थव्यवस्था को 0.75 फीसदी का सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। वक्त यह समझने का है कि 2008 वाली मंदी अगले एक–दो वर्षों में दोबारा लौटी तो उससे निपटना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा।

करतारपुर साहिब खोलने का फैसला

(जी.एन.एस.), पाकिस्तान ने करतारपुर साहिब गलियारा खोलने का फैसला लिया है। यह सिख श्रद्धालुओं के लिए बड़े राहत की बात है। गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के मद्देनजर भारत के सिख श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर साहिब गलियारा खोलने का पाकिस्तान का फैसला बहुत बड़ी राहत है। न केवल पिछले 70 साल से इस फैसले का इंतजार कर रहे सिख श्रद्धालु इस फैसले से गदगद हैं बल्कि भारत–पाकिस्तान के ठंडे पड़ते रिश्तों में भी इससे नई गरमाहट आ सकती है। करतारपुर साहिब सिखों के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में शुमार होता है।

यह स्थान भारतीय सीमा से करीब चार किलोमीटर दूर है और इतनी सी दूरी के चलते भारतीय सिखों को दूरबीन से अपने इस पवित्र गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करके संतोष करना पड़ता था। दोनों देशों में बनी नई सहमति के अनुसार भारत सरकार गुरदासपुर जिला स्थित डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक कॉरिडोर का निर्माण करेगी और पाकिस्तान सरकार सरहद से करतारपुर साहिब तक। श्रद्धालुओं को सीमा पर स्लिप दी जाएगी, जिसके आधार पर वे करतारपुर साहिब तक आसानी से पहुंचेंगे और दर्शन करके शाम तक वापस लौट आएंगे। इस फैसले ने बताया है कि संबंधों के बुरे दौर में भी सौहार्द बनाने वाले कुछेक कदमों के जरिए माहौल को मैत्रीपूर्ण बनाया जा सकता है। कूटनीति की तुला में क्या उक्त कदम कट्टर सिक्ख समुदाय को आकर्षित करने में सफल होगा?? अच्छा हो की इमरान ख़ान कटासराज तक्षशिला न सही पर पकी कब्जे में कश्मीर में करतारपुर से कोई सभी पिछले कुछ वर्षों से भारत–पाकिस्तान संबंधों में सुधार के सारे उपाय नाकाम होते दिखे। जब भी कोई पहल होती, आतंकवाद से जुड़ी कोई न कोई ऐसी घटना होती जो उस पहल को बेअसर कर देती। आखिर भारत ने यह स्टैंड ले लिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ–साथ नहीं चल सकते। दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसा कोई कदम नहीं उठा सका जिससे यह लगे कि वहां आतंकवाद की नकेल कसी जा रही है। स्वाभाविक रूप से नए प्रधानमंत्री इमरान खान का बातचीत का प्रस्ताव कारगर नहीं साबित हुआ। लेकिन औपचारिक बातचीत न करते हुए भी दोनों पक्षों ने करतारपुर साहिब संबंधी प्रस्ताव को आगे बढ़ाया और पाकिस्तान ने इस पर उपयुक्त फैसला किया, जो बताता है कि संबंधों में सुधार की इच्छा दोनों तरफ कायम है। हालांकि दोनों ही तरफ संबंधों को बिगाड़ने की इच्छा रखने वाले तत्व भी बड़ी संख्या में हैं। वक्त की जरूरत यह है कि दोनों देशों में माहौल बिगाड़ने वालों की साजिशों को समझा जाए और इन साजिशों को हर हाल में नाकाम करने का संकल्प कमजोर न पड़ने दिया जाए। इसका एक अच्छा तरीका यह हो सकता है कि दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंधों में आम लोगों की अधिकाधिक दिलचस्पी पैदा की जाए। यानी पीपल टु पीपल कंटैक्ट बढ़ाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। व्यापार को अधिक से अधिक बढ़ाने के उपाय किए जाएं। ये सब होगा तो आतंकी और विघ्नकारी तत्व अपने आप हाशिये पर पहुंचते जाएंगे और कभी इक्का–दुक्का भड़काने वाली घटनाएं हो भी गईं तो उनका आम लोगों की भावनाओं पर ज्यादा असर नहीं होगा।

जियोनी के चेयरमैन की 1 खरब रुपये जुए में हारने की खबर, दिवालिया होने की कगार पर कंपनी

जियोनी के चेयरमैन ने भी करीब 1000 करोड़ रुपये जुए में हारने की बात स्वीकार कर ली है। कहा जा रहा है कि जियोनी अपने सप्लायर्स को पेमेंट नहीं दे पाई। नशे में धुत मॉडल ने लिफ्ट के अंदर क्यों उतारे कपड़े ?नशे में धुत मॉडल ने लिफ्ट रेसलिंग के रिंग में महिला रेसलर से बुरी तरह पिटीं राखी सावंतरेसलिंग के रिंग मं महिला शख्स ने यूं दिया मौत को चकमा, विडियो देख चौक जाएंगे आपशख्स ने यूं दिया मौत को चक लड़कियां इग्नोर करती हैं इसलिए रेप होते हैं ग्मालविका मोहननलड़कियां इग्नोर करती हैं चीनी वेबासइट की रिपोर्ट,स्ड्ढह्व स्ड्ढह्वश्वठ्ठजुआ खेलते वक्त कथित तौर पर 10 अरब युआन हार गए

स्ड्ढह्व स्ड्ढह्वश्वठ्ठ ने खुद माना कि वह 10 अरब रुपये जुए में हार गए हैं

एक अन्य वेबसाइट Jiemian के मुताबिक, करीब 20 सप्लायरों ने कोर्ट में दिवालियेपन का आवेदन दिया. अप्रैल महीने में जियोनी ने कहा था कि वह भारत में इस वर्ष 6.5 अरब रुपये निवेश करेगी.

दुबई से मुंबई के बीच पानी के नीचे चलेगी ट्रेन?

हाइपरलूप और ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार के बाद यूएई भविष्य के एक और महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट

(जी.एन.एस.),

यात्रियों को ढोने के अलावा तेल और अन्य सामानों का होगा आयात–निर्यात हकीकत में बदला तो 2 हजार किलोमीटर का होगा रेल नेटवर्क

हाइपरलूप और ड्राइवरलेस फ्लाइंग कार के बाद यूएई भविष्य के एक और महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट पर विचार कर रहा है, जो भारत से जुड़ा है। निकट भविष्य में दुबई से मुंबई के बीच समुद्र के नीचे रेल दौड़ सकती है। खलीज टाइम्स के मुताबिक, अबु धाबी में यूएई–इंडिया कॉनक्लेव के दौरान नैशनल अडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अलशेही ने इसका खुलासा किया। अलशेही कंसल्टेंट फर्म नैशनल अडवाइज ब्यूरो लिमिटेड के फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि पानी के नीचे इस रेल नेटवर्क से यूएई–भारत के अलावा क्षेत्र के दूसरे देशों को भी फायदा होगा। यात्रियों के अलावा तेल और अन्य सामानों के आयात–निर्यात के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने कहा, यह एक विचार है। हम भारतीय शहर मुंबई को फूजेरा के साथ पानी के नीचे बेहद तेज गति वाले रेल नेटवर्क से जोड़ना चाहते हैं। इससे द्विपक्षीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा।

भारत को तेल का निर्यात किया जाएगा और नर्मदा से अतिरिक्त पानी का आयात किया जाएगा। उन्होंने कहा, इस योजना पर अभी कई दृष्टिकोण से विचार करने की जरूरत है। हम प्रॉजेक्ट के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। यदि यह विचार हकीकत में बदलता है तो रेल नेटवर्क करीब 2000 किलोमीटर का होगा। बतादें, दुनिया में इस तरह के कई प्रॉजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं। चीन रूस, कनाडा और अमेरिका को कनेक्ट पर विचार कर रहा है। भारत में मुंबई और

बड़े शहरों के लिए सीख है सूरत मॉडल, प्रवासियों के लिए नगर निगम चला रहा 120 स्कूल

(जी.एन.एस.),प्रवासी मजदूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए गुजरात का सूरत नगर निगम 120 स्कूलों की सुविधा दे रहा है। ये गैर गुजराती मीडियम स्कूल हैं जहां हिंदी और इंग्लिश के अलावा मराठी, उड़िया, तेलुगू और उर्दू मीडियम स्कूल भी हैं। इन स्कूलों की अवधारणा 90 के दशक के आखिर में रखी गई थी।प्रवासी की बड़ी आबादी वाले शहरों को सूरत से सीख लेनी चाहिए जहां नगर निगम कार्यबल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 120 विशेष स्कूल चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इन स्कूलों में गुजराती के अलावा कई और भाषाएं भी पढ़ाई जाती हैं जिससे प्रवासी कर्मचारी अपने परिवार को भी शहर में बसा रहे हैं। इन गैर गुजराती मीडियम स्कूलों में 66 हजार से भी ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और यह संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है। सूरत टेक्सटाइल और हीरों का हब माना जाता है। बड़ी संख्या में हिंदी भाषी राज्यों जैसे ओडिशा और आंध्र प्रदेश से लोग इस शहर में प्रवास करते हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि कक्षा 1 से 3 तक प्राइमरी स्टैंडर्ड की सुविधा वाले अधिकतम 55 स्कूल मराठी माध्यम में हैं, इसके बाद 28 उर्दू माध्यमिक विद्यालय हैं। सूरत नगर निगम के तहत 7 उड़िया मीडियम स्कूल और 4 तेलुगू मीडियम स्कूल हैं। एक अधिकारी ने बताया, हमारे पास 25 हिंदी मीडियम और 9 इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं।

हमने मराठी और हिंदी मीडियम में सेंकडरी कक्षाएं शुरू की हैं ताकि प्रवासियों के बच्चों को पर्याप्त शैक्षिक सुविधा मिल सके। वह आगे कहते हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि अधिकतर प्रवासी जो यहां काम के लिए आते हैं वे प्राइवेट स्कूलों का खर्च वहन कर सकते हैं। हम शायद एकमात्र नगर निकाय होंगे जो कई भाषाओं में स्कूल चलाते हैं।

नगर निगम के सूत्र के मुताबिक, दूसरे शहरों से सूरत में काम करने के लिए आने वाले ज्यादातर मजदूरों को देखते हुए इन स्कूलों की अवधारणा 90 के दशक के आखिर में रखी गई थी। इसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार, शहर की जनसंख्या में 30 फीसदी प्रवासी शामिल थे। आवासीय एवं शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, ऊंची इमारतें और आइकॉनिक स्ट्रक्चर के निर्माण के बजाय एक स्मार्ट सिटी कहलाने के लिए एक शहर की यह नरम विशेषताएं हैं। सूरत समाज के विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने समावेशी दृष्टिकोण के लिए एक मॉडल है।

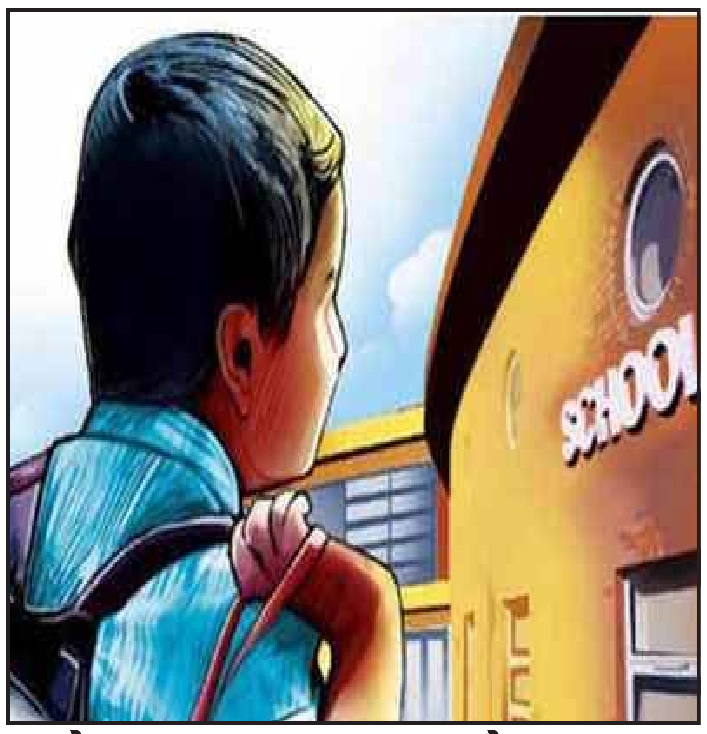

ये गैर गुजराती मीडियम स्कूल हैं जहां हिंदी और इंग्लिश के अलावा मराठी, उड़िया, तेलुगू और उर्दू मीडियम स्कूल भी हैं

अहमदाबाद कलेकटर ऑफिस पर दलित समाज के लोगों ने उना काण्ड को लेकर आवेदनपत्र दिया। (संपूर्ण समाचार सेवा)

BSF ने जताई चिंता, राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में बदल रही है डिमॉग्रफी

(जी.एन.एस.), हाल ही में बीएसएफ ने पाकिस्तान से लगते राजस्थान के जैसलमेर जिले पर एक सर्वे किया था, जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। स्टडी में सामने आया है कि पाकस्तान बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। ने पाकिस्तान से लगते राजस्थान के जैसलमेर जिले में असाधारण रूप से डिमॉग्रफी में बदलाव पर गहरी चिंता जताई है अन्य समुदायों की 8–10 प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि की तुलना में जैसलमेर बॉर्डर पर मुस्लिमों की आबादी में 20–22 पर्सेंट की बढ़त बीएसएफ ने हाल ही में स्टडी की थी और सीमाई इलाकों में डिमॉग्रफी बदलने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को जानकारी दी है बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने पाकिस्तान से लगते राजस्थान के जैसलमेर जिले में असाधारण रूप से डिमॉग्रफी (जनसांख्यिकी) बदलने को लेकर गहरी चिंता जताई है और इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी जानकारी दी। बीएसएफ की स्टडी में यह बात सामने आई है कि सीमाई इलाकों में मुस्लिमों में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है और वे अपनी पारंपरिक राजस्थानी पहचान के बजाय अरब की परंपराओं को तवज्जो देने लगे हैं। यहां के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय स्वीकार कर रहे हैं कि उनके बीच बातचीत का दायरा सिकुड़ रहा है। हाल ही में बीएसएफ ने जैसलमेर के सीमाई इलाकों की डिमॉग्रफी को लेकर एक स्टडी की थी और उसमें काफी चौंकाने वाली बातें सामने आईं। लोगों के हेयरस्टाइल से लेकर पहनावे तक में राजस्थानी कल्चर गायब हो चुका था। इस स्टडी में यह भी सामने आया कि अन्य समुदायों की तुलना में जैसलमेर बॉर्डर पर मुस्लिमों की आबादी में तकरीबन 22–22 पर्सेंट तक की बढ़त हुई। दूसरी तरफ, अन्य समुदायों की आबादी में 8 से 10 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

विश्व एड्स दिन के अवसर पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल में बच्चो को गिफ्ट भी दी गई। (संपूर्ण समाचार सेवा)

अमेरिका में रहने वाला प्रवासी भारतीय वडोदरा से लापता

(जी.एन.एस.). वडोदरा, (भाषा) अमेरिका में रहने वाले एक प्रवासी भारतीय (एनआरआई) वडोदरा से लापता हो गए। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। लापता एनआरआई कालेज स्तर के पूर्व क्रिकेटर भी हैं। पुलिस उपायुक्त (अपराध) जयदीप सिंह जडेजा ने बताया कि मित्तल सरैया का पता लगाने के लिए अपराध शाखा ने चार टीमों का गठन किया है। सरैया मंगलवार से लापता हैं।
उन्होंने पीटीआई से कहा कि मित्तल सरैया कल शहर में एक निजी बैंक की एक शाखा में गए थे। उसके बाद से वह लापता हैं।सरैया (51) अमेरिका के फ्लोरिडा में रहते हैं। वह अपने बीमार चाचा को देखने सोमवार को यहां पहुंचे थे।
सरैया करीब एक दशक बाद यहां आए थे और शनिवार को अमेरिका लौटने वाले थे। पुलिस मामले में जांच कर रही है।

बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स ने जताई चिंता

राजस्थान में पाक सीमा से सटे इलाकों में बदल रही है डिमॉग्रफी

सीमाई इलाको में मुस्लिमों में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है और वे अरब की परंपराओं को तवज्जो देने लगे हैं

(संपूर्ण समाचार सेवा) वॉशिंगटन, १ दिसम्बर। बॉर्डर सिक्यॉरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने पाकिस्तान से लगते राजस्थान के जैसलमेर जिले में असाधारण रूप से डेमॉग्रफी (जनसांख्यिकी) बदलने को लेकर गहरी चिंता जताई है और इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी जानकारी दी। बीएसएफ की स्टडी में यह बात सामने आई है कि सीमाई इलाको में मुस्लिमों में धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है और वे अपनी पारंपरिक राजस्थानी पहचान के बजाय अरब की परंपराओं को तवज्जो देने लगे हैं। यहां के हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय स्वीकार कर रहे हैं कि उनके बीच बातचीत का दायरा सिकुड़ रहा है।

हाल ही में बीएसएफ ने जैसलमेर के सीमाई इलाकों की डिमॉग्रफी को लेकर एक स्टडी की थी और उसमें चौंकाने वाली बातें सामने आई।

लोगों के हेयरस्टाइल से लेकर पहनावे तक में राजस्थानी कल्चर गायब हो चुका था। इस स्टडी में यह भी सामने आया कि अन्य समुदायों की तुलना में जैसलमेर बॉर्डर पर मुस्लिमों की आबादी में तकरीबन २२–२२ पर्सेंट तक की बढ़त हुई। दूसरी तरफ, अन्य समुदायों की आबादी में ८ से १० प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है।

बीएसएफ ने अपनी इस स्टडी के जरिए जैसलमेर बॉर्डर पर बढ़ती मुस्लिम आबादी के बारे में आगाह किया है, लेकिन वहां किसी भी तरह की संदिग्ध या फिर कोई भी ऐसी गतिविधि सामने नहीं आई है जो राष्ट्रहित के खिलाफ हो। बीएसएफ के मुताबिक, उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच आज तक किसी भी तरह का विवाद नहीं हुआ है और दोनों समुदायों के लोगों के बीच दोस्ताना संबंध है और वे अपना काम–धंधा भी मिलकर करते हैं। बीएसएफ ने अपनी इस स्टडी में हिंदुओं के उन राइट विंग संगठनों के बारे में भी बताया गया है, जिनके खिलाफ मुस्लिम समुदाय हमेशा से रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, हिंदू राइट विंग संगठनों की गतिविधियों की वजह से मोहनगढ़, नचना और पोखरण में रहने वाले हिंदू अब अपने धर्म को लेकर और ज्यादा चिंतित हो गए हैं।

एक रिसेप्शन दिल्ली और एक मुंबई में होगा

हो गई शादी, एक–दूजे के हुए निक जोनस और प्रियंका

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई, १ दिसम्बर। इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है और बॉलिवुड की चहेती स्टार और ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा इंटरनैशनल पॉप स्टार निक जोनस के साथ कैथलिक रीति–रिवाज से शादी के बंधन में बंध चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा ने इस खास दिन कस्टम मेड रॉल्फ रॉरेन गाउन और निक ने भी रॉल्फ लॉरेन टक्सीडो पहना था।

रिपोर्टस के मुताबिक जोनस ब्रदर्स केविन और जो प्रियंका के भाई सिद्धार्थ के साथ ग्रूस्समेन के रूप में रहे वहीं ईशा अंबानी, अर्पिता खान शर्मा और परिणीति चोपड़ा ब्राइड्समेड थीं। बताया जा रहा है कि निक जोनस के पिता पॉल केविन जोनस सीनियर ने प्रियंका के स्वर्गीय पिता अशोक चोपड़ा की भूमिका निभाई और उनका हाथ निक जोनस के हाथ में दिया।

प्रियंका और निक की फैमिली २९ नवंबर को जोधपुर के उम्मेद भवन पैलेस पहुंचे थे, इसके बाद उनके रिलेटिव्स और दोस्तों का आना जारी है। बता दें कि इस वेडिंग सेरिमनी के लिए खास सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। वेन्यू पर मोबालि फोन रखने की अनुमति भी नहीं है। प्रियंका के

फैंस उनकी शादी की तस्वीरों और डिटेल्स जानने के लिए बेचैन हैं। शादी के बाद दो रिसेप्शन होंगे। एक रिसेप्शन दिल्ली और एक मुंबई में होगा।

प्रियंका चोपड़ा ने कस्टम मेड रॉल्फ रॉरेन गाउन और निक जोनस ने भी रॉल्फ लॉरेन टक्सीडो पहना था

गुजरातः नशे में धुत डॉक्टर ने की महिला की सर्जरी, मां और नवजात की मौत, अरेस्ट

(जी.एन.एस.)बोटाद, गुजरात के बोटाद में नशे में धुत एक डॉक्टर ने महिला की डिलीवरी कराने के लिए सर्जरी की। सर्जरी के दौरान महिला के बच्चे और कुछ देर बाद महिला ने दम तोड़ दिया। घरवालों की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।

गुजरात में इलाज के दौरान लापरवाही के एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां बोटाद सरकारी अस्पताल में एक डॉक्टर ने नशे में धुत होकर महिला की सर्जरी करके प्रसव कराया। प्रसव के दौरान नवजात की और कुछ ही घंटों बाद महिला की मौत हो गई। मामला खुलने के बाद आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि आलमपुर गांव की कामिनी चाची को सोमवार शाम को सोनावाला अस्पताल में लेबर पेन के बाद भर्ती कराया गया था। यहां एमबीबीएस डॉक्टर और अस्पताल के रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर परेश लखानी (50) ने कामिनी की सर्जरी करने की बात कही। वह उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहां उसका सिजेरियन किया। सिजेरियन के दौरान बच्चे का मृत पैदा होना बताया गया। वहीं कामिनी को लगातार तेज ब्लीडिंग हो रही थी। उसकी हालत खराब होने पर घरवाले उसे बोटाद के एक महिला रोग विशेषज्ञ के प्राइवेट क्लीनिक ले गए जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कामिनी के घरवाले वापस सोनावाला अस्पताल आए और वहां डॉ. लखानी से बात की। उन्होंने पाया कि डॉ. लखानी नशे में हैं। पूछने पर पता चला कि उन्होंने शराब पीकर कामिनी के सर्जरी की थी। उन लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने प्राथमिक जांच और ब्रीथ ऐनालाइजर टेस्ट में पाया कि डॉ. लखानी नशे में थे। एसपी हर्षद मेहता ने बताया कि कामिनी के परिजनों ने डॉ. लखानी पर मेडिकल नेगलिजेंस का आरोप लगाया है। हम लोगों ने भावनगर के सर टी हॉस्पिटल को जांच करके कामिनी की मौत का सही कारण पता कराने को कहा है। अगर जांच में कमिटी ने चिकित्सीय लापरवाही पाई तो डॉ. लखानी के खिलाफ अलग से केस दर्ज किया जाएगा।

डबल मर्डर- बेटी को मार नदी में फेंका, 260 किलो सीमेंट से वाटर टैंक में ढक दिया मां का शव

(जी.एन.एस.)वडोदरा गुजरात के दाहोद जिले में किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की तरह एक डबल मर्डर केस का खुलासा हुआ है। पिछले दिनों गुमशुदा मां–बेटी की लाश मिलने के साथ ही पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले से पर्दा उठा दिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने एक वाटर टैंक में करीब 260 किलोग्राम सीमेंट के नीचे महिला का शव दफन किया था। वहीं बेटी को नदी में फेंक दिया था।

सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस इस हत्या के खुलासे के काफी करीब पहुंच गई। दरअसल, इनके जरिए पुलिस को यह पता चला कि नंदा अपनी दोस्त और सहकर्मी मंजू भभोर पुलिस के मुताबिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नंदा सिसोदिया और उनकी गोद ली हुई बेटी शियोना (3 वर्ष) बीते 17 नवंबर से लापता थीं। 23 नवंबर को लिमखेड़ा के पास एक नदी से शियोना की लाश मिलने के बाद इस पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की।

सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पुलिस इस हत्या के खुलासे के काफी करीब पहुंच गई। दरअसल, इनके जरिए पुलिस को यह पता चला कि नंदा अपनी दोस्त और सहकर्मी मंजू भभोर के घर पर अंतिम बार अपनी बेटी के साथ दिखी थीं। इसके बाद से ही वह और उनकी बेटी गायब हो गई थीं। इसके बाद पुलिस ने भभोर और उनके पति दिलीप को पूछताछ के लिए बुलाया।

पुलिस के मुताबिक कड़ाई से पूछताछ करने पर दंपती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दाहोद पुलिस इंस्पेक्टर केजी पटेल ने बताया कि 17 नवंबर को दंपती ने गला दबाकर नंदा की हत्या कर दी। इसके बाद दंपती ने नंदा की मासूम बेटी को भी इस डर से मार दिया कि वह किसी को इस घटना के बारे में बता न दे। दंपती ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने नंदा की बेटी को मरने के लिए नदी में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस को अभी इस बयान पर शक है।

न आए दुर्गंध, डाल दिया सीमेंट

दंपती ने पुलिस को यह भी बताया कि हत्या करने के बाद उन्होंने नंदा की लाश को दाहोद–गोधरा रोड स्थित अपने घर के पीछे एक वाटर टैंक में डाल दिया। 18 नवंबर को दंपती ने एक अन्य व्यक्ति रोहित की मदद से करीब 14 बोरी सीमेंट लाकर वाटर टैंक में डाल दिया ताकि शव से कोई दुर्गंध न आए और किसी को यह राज पता न चल सके। दंपती की तरफ से जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने मशीन के जरिए वाटर टैंक से सीमेंट की परत हटवाकर नंदा का शव बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी दंपती पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में हैं।

गुजरात- अहमदाबाद में पिछले 5 साल में सेक्स चेंज सर्जरी के मामले दोगुने

(जी.एन.एस.)अहदाबाद, अहदाबाद के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉ.पीके बिलवानी 1977 से अब तक करीब 47 सेक्स चेंज सर्जरी कर चुके हैं। इतना ही नहीं अभी उनके पास ऐसे 5 मामले और हैं। बिलवानी कहते हैं, सेक्स चेंज सर्जरी के मामले पिछले कुछ वर्षों मे तेजी से बढ़े हैं।

गुजरात के अहमदाबाद में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनने के लिंग परिवर्तन (सेक्स चेंज) ऑपरेशनों के मामले पिछले पांच वर्षों में दोगुना हो गए हैं। अहमदाबाद के मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुाबिक पांच साल पहले जहां साल भर में ऐसे सिर्फ चार या 5 मामले सामने आते थे, अब इनकी संख्या बढ़कर 10 (एक साल में) हो गई है। यह आंकड़ा अभी सिर्फ अहमदाबाद शहर का है।

अहदाबाद के मशहूर प्लास्टिक सर्जन डॉ.पीके बिलवानी 1977 से अब तक करीब 47 सेक्स चेंज सर्जरी कर चुके हैं। इतना ही नहीं अभी उनके पास ऐसे 5 मामले और हैं। बिलवानी कहते हैं, सेक्स चेंज सर्जरी के मामले पिछले कुछ वर्षों मे तेजी से बढ़े हैं। मनोचिकित्सक डॉ. अमृत बोदानी भी बिलवानी से समहत दिखते हैं। बोदानी बताते हैं, इस वर्ष इस तरह के मामले (सेक्स चेंज) में मैंने करीब 10 लोगों को सलाह दी है। दरअसल, विशेषज्ञों के मुताबिक आइडेंटिटी डिसऑर्डर डिस्फोरिया के कारण भी बड़े पैमाने पर लोग लिंग सर्जरी के लिए आगे रहे हैं। दरअसल, इस तरह के मामले में मरीजों को उनके लिंग (जन्म से) के विपरीत उनकी सोच और पहनावा होता है। उदाहारणस्वरूप अगर इस समस्या से कोई पुरुष परेशान है तो भले ही उसकी शारीरिक संरचना पुरुषों जैसी हो, मगर उसे लड़कियों की तरह जीने में अच्छा लगता है। इसी तरह अगर वह महिला है, तो वह पुरुषों की तरह रहना चाहती है। मेरे बाद सर्जरी के लिए पांच और लोग आगे आए उधर, वर्ष 2015 में सेक्स सर्जरी कराने वाली आकृति पटेल कहती हैं, मेरे सफल ऑपरेशन के बाद वडोदरा से ही पांच और लोग सेक्स चेंज सर्जरी के लिए आगे आए। मैं जानती हूं कि बहुत सारे और लोग हैं, जो सेक्स चेंज कराना चाहते हैं लेकिन सामाजिक लांछन के डर से वे ऐसा कर नहीं पा रहे हैं।

दूसरे हाफ में बदली गयी रणनीति का फायदा मिला- हरेंद्र

भुवनेश्वर, दो दिसंबर (भाषा) भारत के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि रविवार को पुरूष हाकी विश्व कप के पूल सी में बेल्जियम के खिलाफ 2–2 से ड्रा रहे मुकाबले में शुरूआत में गोल गंवाने के बाद हाफ टाइम में बदली गयी रणनीति टीम के लिये कारगर रही। भारत ने आठवें मिनट में गोल गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद टीम ने वापसी करते हुए 2–1 से बढ़त बना ली। लेकिन बेल्जियम ने हूटर बजने से चार मिनट पहले गोल कर स्कोर 2–2 से बराबर कर लिया। हरेंद्र ने कहा कि वह बेल्जियम की शुरू में दबाव बनाने यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटो–अपलोड हुआ है। इसे नवभारतटाइम्स.कॉम की टीम ने एडिट नहीं किया है। भुवनेश्वर, दो दिसंबर (भाषा) भारत के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि रविवार को पुरूष हाकी विश्व कप के पूल सी में बेल्जियम के खिलाफ 2–2 से ड्रा रहे मुकाबले में शुरूआत में गोल गंवाने के बाद हाफ टाइम में बदली गयी रणनीति टीम के लिये कारगर रही। भारत ने आठवें मिनट में गोल गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद टीम ने वापसी करते हुए 2–1 से बढ़त बना ली। लेकिन बेल्जियम ने हूटर बजने से चार मिनट पहले गोल कर स्कोर 2–2 से बराबर कर लिया। हरेंद्र ने कहा कि वह बेल्जियम की शुरू में दबाव बनाने की रणनीति से हैरान नहीं थे। उन्होंने मैच के बाद कहा, ''बेल्जियम के पहले क्वार्टर में दबाव बनाने से हम हैरान नहीं थे। हमने इसके बारे में चर्चा की थी। वे जानते थे कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, भारतीय टीम खतरनाक हो जायेगी। मेरे खिलाड़ियों ने दर्शकों के उत्साह का फायदा उठाया।'' उन्होंने कहा, ''पहले हाफ में हम गेंद के पीछे भाग रहे थे, हम इस पर इतना नियंत्रण नहीं बना पा रहे थे। हमने हाफ टाइम में रणनीति में थोड़ा बदलाव किया। यह हमारे लिये कारगर रहा।'' उन्होंने कहा कि तीसरे और चौथे क्वार्टर में बेल्जियम थोड़ी कमजोर पड़ गयी थी। उन्होंने कहा, ''हमने डबल टैकलिंग की। हम गेंद के पीछे थे या इसका पीछा कर रहे थे, हमने तेजी बनाये रखी।'' हरेंद्र ने कहा कि भारत के प्रदर्शन में फिटनेस ने अहम भूमिका अदा की। उन्होंने कहा, ''मुझे अपनी टीम की फिटनेस पर गर्व है। इसका श्रेय रोबिन अर्केल को जाता है। मैंने कभी भी इतनी फिट भारतीय टीम नहीं देखी।'' उन्होंने कहा, ''हमारे पास गेंद हो या नहीं हो, हम उत्साह कम नहीं कर सकते। हमें अपने प्रतिद्वंद्वी के लिये मुश्किलें पैदा करते रहना जारी रखना होगा।'' भारतीय टीम पूल सी में शीर्ष पर बनी हुई है क्योंकि वह बेल्जियम से गोल अंतर में आगे है। लेकिन हरेंद्र ने कहा कि पूल में अभी भी सभी टीमों के लिये मौका है।
उन्होंने कहा, ''हमारे लिये कोई अगर–मगर की बात नहीं है।

विश्व एड्स दिन के अवसर पर कार्यक्रम हुए

८५ प्रतिशत तक एचआईवी जातिय संबंधो से फैलता है

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,१ दिसम्बर। विश्व एड्स दिन को लेकर अहमदाबाद शहर के सिविल अस्पताल सहित राज्य भर में बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। एचआईवी एड्स के बारे में जनजागृति फैलाने के हेतु से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सिविल अस्पताल के मेडिकल सुप्रि. एम एम प्रभाकर ने बताया कि ८० से ८५ प्रतिशत एचआईवी पोजीटीव बिनसुरक्षित जातिय संबंध के कारण फैलता है। जिससे नियमित रुप से दवाई लेने की जरुरत होती है। नियमित रुप से दवाई लेने से एड्स की तकलीफ को दुर रखा जा सकता है। सिविल अस्पताल में सक्रिय एन्ट्रीरिट्रो वायरल थेरापी सेन्टर में एचआईवी पोजीटीव और एड्स के मरिजो की असरकारक जांच की जा रही है। उनका इलाज भी चल रहा है। एआरवी सेन्टर को नाको की ओर से सेन्टर फर एक्सीलन्स घोषित किया गया है। सिविल अस्पताल के एआरवी सेन्टर के आंकड़ो पर ध्यान दिया जाए तो एड्स के कारण पिछले कुछ वर्षो की तुलना में मृत्यु दर घटा है। पिछले कुछ सालो में मृत्यु दर २८ से ३० प्रतिशत के आसपास था जो घटकर अब २२ प्रतिशत के आसपास रह गया है। इसी तरह सगर्भा माता से गर्भस्थ शीशु को चेप लगने से हर साल पहले ४५ से ५५ केस दर्ज होते थे वह घटकर अब ३० से ३५ हो गए है यानी की अब इन केसो की संख्या भी घटी है। २००४ से लेकर २०१८ तक एचआईवी पोजीटीव के २४३२० मरिज दर्ज हुए है। जिन में से १५८५८ मरिज दवाईया ले रहे है। शहर में १ अप्रैल २०१७ से लेकर पांच सितम्बर के एड्स के ३३९२ मरिज दर्ज हुए है।

नियमित रुप से दवाई चलाई जाय तो फायदा होगा

कागड़ापीठ पुलिस स्टेशन विस्तार में स्थित सफल कोम्पलेक्स में लिफ्टमेन के तौर पर काम करने वाले विकलांग को नोटिस बिना दुर किये जाने को लेकर आजभी हंगामां हुआ। बड़ी संख्या में लोग कलेकटर ऑफिस पर पहुंचे। (संपूर्ण समाचार सेवा)

अहमदाबाद में ९ महिने में ही २८ से अधिक ड्राफ्ट टीपी स्कीम मंजुर

अहमदाबाद की आठ ड्राफ्ट के साथ ११ टीपी स्कीम मंजुर

शहरी इलाको के तेज गति से विकास के हेतुसर मंजुरी दी गई : राजकोट की फाइनल टीपी (मुंजका) और गुडा की स्कीम-८ को भी मंजुरी मिली

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद, १ दिसम्बर।

मुख्यमंत्री विजय रुपाणीने शहरी इलाको के अति तेजी से विकास को आगे बढ़ाने के लिए अहमदाबाद की आठ ड्राफ्ट टीपी के साथ कुल ११ टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजुरी दे दी है। अहमदाबाद में सिर्फ ९ महिने में २८ से अधिक ड्राफ्ट टीपी स्कीम मंजुर की गई है। ३००० से अधिक हेक्टर में आयोजन को अंतिम रुप दिया गया है। ड्राफ्ट टीपी में रास्ते, अन्य सुविधाओं का विकास करने के हेतु से मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को सूचना दे दी है। शहरी विस्तारो में तेजी से विकास को आगे बढ़ाने के लिए यह मंजुरी दी गई है। राजकोट की फाइनल टीपी (मुंजका)-गुडाकी स्कीम-८ (सरगासण) को भी मंजुरी दी गई है। उल्लेखनिय है कि मुख्यमंत्री शहरी विकास विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे है। पिछले नव महिने में अहमदाबाद शहर में ही २८ से अधिक ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजुरी देने से ३००० से भी अधिक हेक्टर विस्तार में आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री की ओर से मंजुर की गई ८ ड्राफ्ट टीपी के कारण १००० हेक्टर उपरांत जमीन को सुआयोजित विकास हो सकेगा। अंदाजित १४५० करोड़ के काम भी यह आठ टीपी स्कीम में करने का फैसला किया गया है। टीपी स्कीम में अधिकतर १८ मीटर या उससे अधिक चौड़ाई के रास्तो का भी आयोजन किया गया है। ६० किलोमीटर के रास्तो का लाभ शहर को मिलेगा। इतना ही नहीं १८० हेक्टर जितनी जमीन रास्तो के लिए, १९५ हेक्टर जमीन अर्बन डेवलोपमेन्ट ओथोरिटी ने बाग बगीचा, खुली जमीन, सोशियल इन्फ्रास्ट्रकचर फेसिलिटी और आर्थिक सामाजिक वर्ग के लोगो के निवासी स्थानो, वाणिज्य आवास की बिक्री से मिलेगी। विजय रुपाणी ने ११ स्कीम को मंजुरी दे दी है। ड्राफ्ट टीपी स्कीम के तहत बहुत सी बाते शामिल की गई है। रुपाणी ने जो ११ स्कीम को मंजुरी दी है उनमें १०-बी काणीटी, ४१९ (असलाली), ४१५ कठवाडा, ५१७ कणभा-कुंजाड, ९१ सनाथल-तेलाव, धानज-पलसाणा, बोरीसणा-कलोल शामिल है। इसके अलावा राजकोट की फाइनल टीपी स्कीन नं.१७ (मुंजका) और सरगासण स्कीम को भी मंजुरी दी गई है।

मुख्यमंत्री का किसानलक्षी एक और निर्णय

खेती विषयक बिजली कनेकशन के लिए राहत

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद, १ दिसम्बर।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने राज्य की प्रवर्तमान स्थिति को ध्यान में लेते हुए एक और अधिक किसानलक्षी निर्णय किया है। जिसके चलते राज्य में डार्क जोन में शामिल ५७ तहेसीलो में अब किसानो को कृषि विषय बिजली कनेकशन लेने के लिए ड्रिप या स्पीन्कलर पद्धति अनिवार्य रुप से अपनाने की जरुरत नहीं होगी। उर्जा मंत्री सौरभ पटेल ने किसान हितलक्षी निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पहले राज्य सरकार ने भूगर्भ जल स्तर नीचे पहुंचने से हुई परेशानी के चलते राज्य के ५७ तहेसीलो को डार्क जोन घोषित किया था जिसके चलते अब किसानो को कृषि विषयक बीजली कनेकशन लेने के लिए अनिवार्य रूप से सुक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाने की जरूरत रहती थी। किन्तु अब इसकी जरूरत नहीं पडेगी। इस साल मोनसून की सिजन में कम बारिश के चलते बहुत से तहेसीलो में स्थिति खराब हुई है। इस बात को ध्यान में लेते हुए कृषि विषयक बिजली कनेकशन लेने से किसानो को मुक्ति दी गई है। गुजरात सरकार पिछले दिनो से किसानो के हित में एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है।

एक और देश के किसान नाराज दिख रहे हैं। दुसरी ओर गुजरात सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है।

स्प्रीन्कलर और ड्रीप इरीगेशन अपनाने की जरूरत नहीं

वलसाड में भी न्यूनतम तापमान १३.६ डिग्री दर्ज

गुजरात में ठंडी और अधिक बढ़ी : नलिया में पारा १२.२

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद, १ दिसम्बर।

अहमदाबाद सहित गुजरात के बहुत से इलाको में अब ठंडी का अनुभव हो रहा है। आज राज्य के बहुत से इलाको में न्यूनतम तापमान शुक्रवार की तुलना में और अधिक गिरने से ठंडी बढ़ गई है। आज नलिया में न्यूनतम तापमान घटकर १२.२ डिग्री दर्ज हुआ। इसके अलावा वलसाड में भी न्यूनतम तापमान घटकर १३.६ डिग्री दर्ज हुआ। अहमदाबाद शहर में सुबह के वक्त लोगों ने अधिक ठंड का अनुभव किया किन्तु दोपहर के समय मिश्र सिजन का अनुभव हुआ। शाम के वक्त भी शहर में लोगों को ठंडी का अनुभव हो रहा है। दुसरी और मौसम विभाग ने बताया है कि अगले दो तीन दिनों के दौरान प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई अधिक परिवर्तन नहीं होगा। सौराष्ट्र और कच्छ की बात की जाए तो अधिकांश इलाको में पारा १६ डिग्री से लेकर १८ डिग्री के बीच रहा। अहमदाबाद के लिए बताया गया है कि कल रविवार के दिन अधिकतम तापमान २९.४ डिग्री और न्यूनतम तापमान आज के स्तर पर रह सकता है। ठंडी में एका

मणीनगर में लेक फ्रन्ट उपरांत शहर के अन्य बाग बगीचो में भी सुबह के वक्त कसरत के इरादे से लोंग जुटने लगे

एक बढौतरी होने से सुबह के वक्त बड़ी संख्या में लोग फिटनेस को लेकर और अधिक सक्रिय दिख रहे हैं। सुबह के वक्त अधिकतर बाग बगीचो में लोगों की भीड़ जुट रही है। मणीनगर इलाके में स्थित लेक फ्रन्ट पर भी बड़ी संख्या में लोग सुबह के वक्त जमा हो रहे है। लेक फ्रन्ट में सुबह ६ से ८ बजे तक लोगों को कोई भी फिस के बिना प्रवेश की मंजुरी होने से बड़ी संख्या में लोग यहा पहुंच रहे है। मौसम विभाग ने बताया है कि सौराष्ट्र-कच्छ के अलावा गुजरात के अधिकांश इलाको में अगले दो दिनो के दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में परिवर्तन नहीं होगा किन्तु छोटे बच्चे और बड़ी आयु के लोगों को इन दिनो में और अधिक सावधानी से आगे बढ़ने की जरुरत है। क्योकि इन्फेकशन और अन्य प्रकार की बिमारीया इन दिनों में अधिक देखी जा रही है।

गुजरात : तापमान.........

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद, १ दिसम्बर।

अहमदाबाद समेत कहां-कितना न्यूनतम तापमान रहा वह निम्न प्रकार है।

स्थल	न्यूनतम तापमान
अहमदाबाद	१६.१
डीसा	१४.४
गांधीनगर	१४.६
वीवी नगर	१७.५
वडोदरा	१६.२
सूरत	१७.५
वलसाड	१३.६
भावनगर	१६
द्वारका	२०.५
ओखा	२४.२
पोरबंदर	१७.२
राजकोट	१६.२
वेरावल	१८.९
दिव	१६
सुरेन्द्रनगर	१७.७
महुवा	१४.१
भुज	१७.३
नलिया	१२.२
कंडला पोर्ट	१५.५
कंडला एयरपोर्ट	१३.८

२७४ करोड़ रुपये की मुंगफली की खरीदी

२७४८३ किसानो के पास से मुंगफली की खरीदी हुई

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद,१ दिसम्बर।

गुजरात सरकार ने किसानो को बड़ी राहत देने के इरादे से उनके पास से समर्थन मुल्य पर मुंगफली खरीदने का निर्णय किया है। जिसके तहत १५ नवम्बर लेकर १दिसम्बर तक राज्य में कुल २७४८३ किसानो के पास से गुजरात सरकरा ने अब तक समर्थन मुल्य पर २७४ करोड़ की कीमत की ५४९२५२ क्वीन्टल मुंगफली खरीदी है। राज्य के अधिकारियों ने बताया है कि सरकार की और से खरीफ सीजन २०१८-१९ के लिए न्युनत्तम समर्थन मुल्य से मुंगफली की खरीदी के लिए १५ नवम्बर से खरीदी शुरु की गई थी। मुंगफली खरीदी के केन्द्र के रुप में घोषित किए गए राज्य के कुल १२२ एपीएमसी सेन्टर पर संबंधित जिल्ला कलेक्टरो की और से १ नवम्बर २०१८ से समर्थन मुल्य पर किसानो के पास से मुंगफली खरीदने के लिए किसानो की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शरु की गई थी। यह रजिस्ट्रेशन के अनुसार सरकार के नियम अनुसार हर रोज २५०० किलोग्राम की मर्यादा की लाने के लिए किसानो को एपीएमसी की और जानकारी दी गई थी। जिसके परिणाम स्वरुप किसान अपनी मुंगफली को बेचने के लिए पहुंचे थे। यह प्रक्रिया के तहत १५ नवम्बर तक राज्य सरकार ने निर्धारित किए गए लघुत्तम समर्थन मुल्य प्रति क्वीन्टल रुपए ५ हजार के अनुसार राज्यभर के २७४८३ किसानो के पास से कुल २७४.६२ करोड़ की कुल ५४९२५२ क्वीन्टल मुंगफली की खरीदी की है। जानकारी में बताया गया है कि खरीद केन्द्रो पर जरुरी संख्या में वजन कांटे रखे गए थे। स्टाफ को भी रखा गया था। हाल हीं में वजन को लेकर शिकायत होने के बाद इस दिशा में पहल की गई है। तीन दिसम्बर से अधिक से अधिक किसानो के पास से मुंगफली की खरीदारी की जाएगी।

भारतीय होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित

एच-१बी वीजा के नियमों को अब और सख्त करेगा अमेरिका

(संपूर्ण समाचार सेवा)
वॉशिंगटन, १ दिसम्बर।

ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को एच-१बी आवेदन प्रक्रिया में कुछ बड़े बदलावों का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित नए नियमों के मुताबिक कंपनियों को अब अडवांस में अपने पिटिशंस का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका उद्देश्य अमेरिका के इस लोकप्रिय वर्क वीजा को सिर्फ सबसे ज्यादा कुशल और सबसे ज्यादा वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को देना है। बता दें कि भारतीय आईटी कंपनियों और प्रफेशनल्स के बीच एच-१बी वीजा काफी लोकप्रिय है। जाहिर है, एच-१बी वीजा प्रक्रिया में प्रस्तावित बदलावों से सबसे ज्यादा प्रभावित भारतीय पेशेवर ही होंगे। अमेरिकी संसद ने एक साल में एच-१बी वीजा की अधिकतम सीमा को तय कर रखा है। उसके मुताबिक एक वित्त वर्ष में अधिकतम ६५,००० एच-१बी वीजा जारी हो सकते है। हालांकि, अमेरिका से ही मास्टर डिग्री लेने वाले या उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विदेशियों के लिए अलग से सालाना २०,००० एच-१बी वीजा जारी किए जाते हैं, जो ६५ हजार की उच्च सीमा के अतिरिक्त है। नए नियमों के मुताबिक युएससीआईएस के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह अमेरिका में उच्च शिक्षा प्राप्त आवेदक को ६५,००० वीजा लिमिट से छूट दे या नहीं। नए प्रस्तावित नियमों के बारे में शुक्रवार को नोटिस जारी किया गया। इसके मुताबिक एच-१बी वीजा पर विदेशी वर्करों की नियुक्ति करने वाली कंपनियों को अब अडवांस में खुद को यूएस सिटिजनशिप ऐंड इमिग्रेशन सर्विसेज पर इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर करना पड़ेगा।

राजस्थान में बीजेपी प्रत्याशी का विवादित वादा

जीत मिली तो बाल विवाह पर पुलिस नहीं करेगी परेशान

वापसी की राह देख रहे बीजेपी के नेता विधानसभा चुनाव में मतदाता को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे है

(संपूर्ण समाचार सेवा)
जयपुर, १ दिसम्बर।

राजस्थान की सत्ता में एक बार फिर वापसी की राह देख रहे बीजेपी के नेता इस बार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे है। चुनाव प्रचार के बीच एक ओर जहां राज्य में चुनावी सभाओं का दौर जारी हैं, वहीं पाली जिले में एक बीजेपी प्रत्याशी ने एक विवादित ऐलान कर पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। पाली जिले की सोजत सीट से प्रत्याशी शोभा चौहान ने वोटरों के बीच अपनी एक सभा में ऐलान किया है कि अगर वह इन चुनावों में विजयी होती हैं तो पुलिस बाल विवाह के किसी भी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। शोभा चौहान के इस विवादित भाषण का विडियो मीडिया में सामने आने के बाद अब इसकी आलोचना शुरू हो गई है। आईएएस अधिकारी राजेश चौहान की पत्नी शोभा पाली की सोजत सीट से दूसरी बार चुनाव लड़ रही हैं। चुनाव को लेकर हुई एक सभा में शोभा ने कहा है कि अगर वह सत्ता में आएंगी तो उनके क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को बाल विवाह के मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई से परेशान नहीं होना होगा। इस भाषण का विडियो सामने आने के बाद पाली जिले के कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने जांच के आदेश दिए है। दूसरी ओर बीजेपी ने इसपर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जिला निर्वाचन अधिकारी और डीएम सुधीर कुमार शर्मा का कहना है कि इस मामले के सामने आने के बाद तत्काल जांच के आदेश दिए गए है। उन्होंने कहा कि विडियो की सत्यता की जांच की जा रही है।

सुरत में ट्राफिक और पार्किंग की समस्या हल होगी

सुरत महानगर की पार्किंग पॉलिसी को मंजुरी मिली

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद, १ दिसम्बर।

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने आज सुरत महानगर की प्रस्तावित पार्किंग पॉलिसी को भी मंजुरी दे दी है। सुरत महानगर में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या और गाडियों के उपयोग के चलते ट्राफिक और परिवहन को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। यह समस्याओं के निवारण के लिए सुरत महानगरपालिका ने प्रस्तावित पार्किंग पोलिसी और पार्किंग बायलोज प्रस्ताव सरकार में प्रस्तुत किये थे। सुरत गुजरातभर में जन संख्या की द्रष्टी से राज्य का सबसे बड़ा दुसरे नंबर का शहर है। हीरे उद्योग समेत अन्य उद्योग में १० लाख से अधिक लोग सुरत में काम कर रहे है। इतना ही नहीं यह महानगर के ६५ किलोमीटर इलाके में जनमार्ग रोज के ३५००० से भी अधिक लोगो को एक जगह से दुसरे स्थान पर पहुंचा ने व्यस्त है। साडे सात लाख लोग सुरत में ओटो रीक्षा, टेक्सी और कार से परिवहन कर रहे है। पिछले एक दशक में बड़ी संख्या में गाडियों के रजिस्ट्रेशन और उपयोग के चलते ट्राफिक और पार्किंग की बड़ी समस्या खडी हुई है।

इस मुद्दे पर चर्चा चल रही थी। राज्य के शहरो में ट्राफिक और पार्किंग की व्यवस्था को सरल रुप से आगे बढ़ाने के हेतु से अभियान चलाए जा रहे हैं। अब सुरत महानगर में प्रस्तावित सुआयोजित पार्किंग पोलिसी को मुख्यमंत्री की ओर से मंजुरी मिलने से सुरत महानगर में ट्राफिक और पार्किंग समस्या से मुक्ति मिलेगी। राज्य सरकार ने सुरत महानगर की पोलिसी को मंजुरी देकर लोगों को और अधिक राहत दी है। सुरत में ओन स्ट्रीट पार्किंग-ओफ स्ट्रीट पार्किंग के लिए सुविधाए नियमित दर से उपलब्ध कराई जाएगी।

नोरा फतेही के बैले डान्स ने दीवाना बना दिया था

नोरा फतेही के 'दिलबर-दिलबार' का अरबी वर्जन

(संपूर्ण समाचार सेवा)
मुंबई, १ दिसम्बर।

बॉलिवुड के इस साल के सुपरहिट गानों में फिल्म 'सत्यमेव जयते' का 'दिलबर-दिलबर' सॉन्ग भी शामिल है। इस गाने में नोरा फतेही के बैले डान्स ने सभी को दीवाना बना दिया था। इस गाने के बाद नोरा फतेही की फैन फॉलोइंग में भी बढ़ोतरी हो गई। अब नोरा ने एक बार फिर इस गाने को एक अलग अंदाज में पेश कर रही हैं। मॉडल से ऐक्ट्रेस बनीं नोरा ने अब इस गाने का अरबी वर्जन पेश किया है। अरबी वर्जन में नोरा ने अपनी आवाज भी दी है। गाने को मोहसिन तिजाफ ने कंपोज किया है जबकि इसे खलिफा मेनानी और अशरफ आरब ने लिखा है। बता दें कि पहली बार यह सॉन्ग सुष्मिता सेन पर फिल्माया गया था। यह १९९९ में आई फिल्म 'सिर्फ तुम' का गाना है। यह अपने समय का सुपरहिट सॉन्ग था और रीक्रिएशन के बाद भी इसे काफी पसंद किया गया।

अरबी वर्जन में बनीं नोरा ने अपनी आवाज भी दी है

चार लोगों को गिरफ्तार किया गया

नाना चिलोड़ा में गैरकानूनी कोल सेन्टर का पर्दाफाश

गिरफ्तार लोगों के पास से लेपटोप, मेजिक जेक जब्त

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद, १ दिसम्बर।

अहमदाबाद शहर में गैरकानूनी रुप से चल रहे कोल सेन्टर को पकड़ने का सीलसीला जारी रहा है। आज एक और कोल सेन्टर का पर्दाफाश किया गया। शहर के नाना चिलोड़ा इलाके में स्थित एक बंगले में से चलाए जा रहे इन्टरनेशनल कोल सेन्टर का पर्दाफाश किया गया है। नरोडा पुलिस ने कोल सेन्टर का पर्दाफाश करते हुए चार युवको को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से दो लेबटोप और मेजिक जेक समेत चीजे जब्त की गई है। लेन्डी क्लब नाम से चलाई जा रही कंपनी में यह चार युवक विदेशी लोगों को लोन और अलग अलग लालची स्कीम में फसाकर जालसाजी कर रहे थे। विदेशी लोगों को फसाकर उनके पास से लाखो रुपये एठ रहे थे। पुलिस ने सभी युवको को गिरफ्तार करके जांच शुरु की है। उल्लेखनिय है कि शहर के मेघाणीनगर इलाके में पुलिस ने थोड़े दिन पहले ही एक बंगले में चलाए जा रहे कॉल सेन्टर का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी के पास से ८४ लाख रुपये नकद जब्त की थी। नरोडा पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद आज कार्रवाई की। शहर के नाना चिलोड़ा इलाके में स्थित वृंदावन बंगले में गैरकानूनी रुप से कोल सेन्टर चलाए जाने के जानकारी मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने छापेमारी करते हुए बंगले में से आरोपी हर्ष पटेल, महेन्द्र उर्फ मोन्टु चावला, निरज उर्फ निरव पटणी और ध्रुव उर्फ बिटु पटेल को रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बंगले में से विदेशी नागरिको के नाम, नंबर की जानकारी भी ली है। लेपटोप, हार्डडीस्क, मेजिक जेक सहित की चीजवस्तुए जब्त की है।

हिंदू भावना के आधार पर सुप्रिम कोर्ट नहीं दे सकता है फैसला

(संपूर्ण समाचार सेवा) हैदराबाद,

अयोध्या विवाद में देरी को राष्ट्री स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने हिंदुओं का अपमान बताया, जिस पर पलटवार करते हुए आईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू भावना के आधार पर फैसला नहीं दे सकता हैं। ओवैसी के अनुसार यहां आस्था और भावना वगैरह प्रासंगिक नहीं है बल्कि केवल इंसाफ होना चाहिए। ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हिंदू भावना के आधार पर फैसला नहीं ले सकता है। वह (आरएसएस) इस बात को मानने को तैयार नहीं कि यहां संविधान नाम भी एक चीज है। आस्था, भावना वगैरह यहां प्रासंगिक नहीं है। बता दें कि संघ ने राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश की मांग फिर से दोहराई है। संघ ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो वह राम मंदिर के लिए १९९२ जैसा आंदोलन भी करेगा। संघ ने कहा कि सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत द्वारा यह कहे जाने पर कि हमारी प्राथमिकता अलग है, इसे हिंदू समाज अपमानित महसूस कर रहा है। संघ के सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राम मंदिर के निर्माण की प्रतीक्षा लंबी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट हिंदू भावना के आधार पर फैसला नहीं दे सकता हैं। ओवैसी के अनुसार यहां आस्था और भावना वगैरह प्रासंगिक नहीं है बल्कि केवल इंसाफ होना चाहिए। ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हिंदू भावना के आधार पर फैसला नहीं ले सकता है

सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई को ७ साल हो गए हैं। जब तीन जजों की पीठ बनी थी तो हमे उम्मीद थी जल्द इसपर कोई निर्णय आएगा। जोशी ने कहा, राम सबके ह्रदय में रहते हैं। भगवान हर कीमत पर राम मंदिर का निर्माण चाहते हैं। हम लगभग ३० सालों से मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कुछ कानूनी बाधाएं अवश्य हैं।

योग गुरु की ओर से लिखी गई नोट मिली

गुरु प्रदीपजी की आत्महत्या की कोशिष से सनसनी फैली

(संपूर्ण समाचार सेवा)
अहमदाबाद, १ दिसम्बर।

सुरत के कामरेज निकट धोरण पारड़ी में सत्यम फाउन्डेशन योग के संचालक और योग गुरु प्रदीपजी ने जंतुनाशक दवा पीकर आत्महत्या करने की कोशिष की है। जिसके चलते सनसनी फैल गई है। योगगुरु प्रदीपजी ने आत्महत्या के प्रयास से पहले एक नोट भी लिखी थी जिसमें १० साधको की और से की जा रही हैरानगति का उल्लेख भी किया है। इसके अलावा दान में दिए गये पैसे वापस करने के लिए धमकिया भी मिल रही थी। धमकिया और प्रेशर के परिणाम स्वरुप आत्महत्या करने जा रहे हैं इस तरह की नोट मिलने से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दुसरी ओर आत्महत्या करने की कोशिष करने वाले योगरुरु प्रदीपजी को होस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। योग गुरु प्रदीपजी की आत्महत्या की कोशिष को लेकर उनके अनुयाईयो और समर्थको में चिंता की लहर दौड गई है। बुहत से साधको में प्रदीपजी को लेकर नाराजगी और आक्रोश भी देखा गया है। जिसे लेकर योग गुरु प्रदीपजी के अनुयाईयो और साधक में विभाजन की स्थिति दिख रही है। इसे लेकर भी एक नया विवाद दिख रहा है। पुरे प्रकरण में पुलिस ने योग गुरु प्रदीपजी की ओर से लिखी गई नोट में उल्लेख किये गए १० साधको की जांच की जा रही है। प्रदीपजी के पत्नी क्रिष्ना बहनने बताया है कि योग और साधना को और अधिक लोगो तक फैलाने के लिए लोगों के पास से योगाश्रम निर्माण के उद्देश्य से प्रदीपजी ने जमीन लेने के लिए साधको ने दान दिया था। साधको की ओर से अचानक रुपये वापस लेने के लिए दबाव लाया गया।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बुश सीनियर का निधन

(संपूर्ण समाचार सेवा)
वॉशिंगटन, १ दिसम्बर।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच.डब्लू.बुश का ९४ साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार ने शुक्रवार को इसकी सूचना दी। सीनियर बुश ने शीतयुद्ध के खात्मे के बाद अमेरिका को आगे बढ़ने में मदद की थी। निधन के समय तक सीनियर बुश अमेरिका के सबसे उम्रदराज जीवित पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म १२ जून १९२४ को मैसाचुसेट्स के मिल्टन में हुआ था।

इसी साल १७ अप्रैल को उनकी पत्नी बारबरा बुश का ९२ साल की उम्र में निधन हुआ था। जॉर्ज एच. डब्लू. बुश अमेरिका के ४१वें राष्ट्रपति थे। वह १९८९ तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। उससे पहले वह १९८१ से १९८९ तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति भी रहे। वह मौजूदा राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे। सियासत में आने से पहले वह अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके थे।

अमेरिका के ४१वें राष्ट्रपति बुश विदेश नीति के अच्छे जानकार थे। वर्ष १९८९ में सोवियत संघ के विघटन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके करीब दो वर्ष बाद उन्होंने इराक के शक्तिशाली नेता सद्दाम हुसैन को पराजित करने के लिए एक अभूतपूर्व गठबंधन भी बनाया। सीआईए के पूर्व प्रमुख रहे बुश केवल एक कार्यकाल के लिए ही सत्ता में रहे। देश की कमजोर अर्थव्यवस्था के चलते वर्ष १९९२ के चुनाव में उन्हें डेमोक्रेट उम्मीदवार बिल क्लिंटन से मात खानी पड़ी। राजनीतिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय आम सहमति के पक्षधर रहे बुश की विचारधारा मौजूदा रिपब्लिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के बिल्कुल विपरीत थी।

मेमनगर रोड सुभाष चौक से विवेकानंद चौक की ओर जाने वाले रास्ते पर एएमसी की ओर से काम किया जा रहा है। जिसके चलते एक और रास्ता बंद किया गया है। (संपूर्ण समाचार सेवा)

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from 131, Dharmanagar Society, Highway Road, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH